दैनिक जागरण

शिक्षा में किया गया निवेश जीवनपर्यंत लाभ देता है

कश्मीर की राह

भले ही यह स्पष्ट न हो कि पाकिस्तान के विदेश सचिव किस खास मकसद से यकायक भारत आए हैं, लेकिन संभावना यही है कि वह भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अपने प्रधानमंत्री का कोई संदेश लेकर आए होंगे ताकि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने को लेकर कोई सहमति कायम हो सके। यह संभावना इसलिए दिख रही है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने अर्से बाद अपना हवाई क्षेत्र खोला है और दूसरे, इमरान खान भारत से संबंध सुधार के लिए व्यग्र दिख रहे हैं। इस व्यग्रता का एक बड़ा कारण पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है। तमाम उपायों के बावजूद पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के चलते पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं कि वह भारत से तनाव जारी रख सके। यह ठीक है कि पाकिस्तान में कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि कश्मीर में दखल जारी रखकर भारत से संबंध नहीं सुधारे जा सकते, लेकिन मुश्किल यह है कि वहां एक तबका अभी भी ऐसा है जो छल-बल से कश्मीर हासिल करने के सपने देख रहा है। इस तबके को ताकत प्रदान कर रही है पाकिस्तानी सेना और जिहादी तत्व। फिलहाल यह कहना कठिन है कि इमरान खान अपनी सेना और अपने यहां के जेहादी तत्वों को यह समझाने में सफल हैं या नहीं कि कश्मीर की रट लगाते रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन भारत से संबंध सुधार उनके हाथ में ही है। अगर पाकिस्तान अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश से संबंध सामान्य नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए वही अधिक जिम्मेदार है। यह पाकिस्तान ही है जिसने संबंध सुधारने के नाम पर भारत को रह-रह कर धोखे दिए हैं। बीते दो दशक तो खास तौर से पाकिस्तान की धोखेबाजी की कहानी ही कहते हैं।

फिलहाल किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि पाकिस्तान से रिश्ते कब और कैसे सामान्य होंगे, लेकिन इस अनिश्चितता का यह मतलब नहीं हो सकता कि कश्मीर को सही रास्ते पर लाने के लिए भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त प्रयास न किए जाएं। कश्मीर के हालात ठीक करने का काम तो प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि मोदी सरकार इस बार और अधिक मजबूती से सत्ता में आई है और उसने अनुच्छेद 370 खत्म करने का वादा भी किया है। इस अनुच्छेद को खत्म करने अथवा उसकी खामियों को दूर करने के उपायों पर काम करते हुए मोदी सरकार को यह भी देखना होगा कि कश्मीर के वर्चस्व को कैसे खत्म किया जाए? जम्मू-कश्मीर की समस्या को केवल घाटी की समस्या के तौर पर देखे जाने के अपने दुष्परिणाम सामने आए हैं। चूंकि कश्मीर ही ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है इसलिए जम्मू और लद्दाख की अनदेखी ही होती है। एक समस्या यह भी है कि कश्मीर की हर छोटी-बड़ी घटना को सदैव गंभीर चुनौती के तौर पर देखा जाता है। इसके चलते वहां अलगाववाद ने एक धंधे का रूप ले लिया है। जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन की तैयारियों के पीछे का सच जो भी हो, उपद्रवग्रस्त घाटी को पटरी पर लाने के लिए हर संभव कदम उठाने का समय आ गया है।

पोस्टकार्ड से वार

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल और भाजपा के बीच जारी तल्खी लोकसभा चुनाव के बाद से और तेज हो गई है। अब तक जय श्रीराम के नारे को लेकर तृणमूल एवं भाजपा में तलवार खींची हुई थी जो अब पोस्टकार्ड वार में तब्दील हो गई है। भाजपा ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्रीराम लिखा 10 लाख पोस्टकार्ड भेजना शुरू किया है तो उधर तृणमूल इस पर पलटवार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 20 लाख पोस्टकार्ड भेजने का निर्णय लिया है, जिस पर जय हिंद, जय बांग्ला लिखा होगा। यह अजूबा सियासी जंग बंगाल में शुरू हो चुकी है। इस जंग का अंत कहां होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पोस्टकार्ड वार छिड़ चुका है। भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन सिंह ने कहा, हमने मुख्यमंत्री के आवास पर 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का निर्णय किया है, जिन पर जय श्रीराम लिखा होगा। भाजपा को उसके ही हथियार से पलटवार करने की तैयारी में तृणमूल भी जुटी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मैं इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित हूं कि आखिर ममताजी को जय श्रीराम के नारे से इतनी दिक्कत क्यों है? 1996 में राम मंदिर आंदोलन के समय से जय श्रीराम का नारा देश भर में प्रसिद्ध है। इसमें कुछ नया नहीं है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहते हुए भी ममता ने कभी इसका विरोध नहीं किया। और हां, हमें जय हिंद से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता अक्सर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हैं। भाजपा के जय श्रीराम नारे के जवाब में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर अपनी डीपी बदल दी। अब उनकी डीपी में जय हिंद, जय बांग्ला लिखा नजर आ रहा है। ममता के साथ ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी डीपी बदल दी है। हमारे देश में जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय जैसे नारे पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर सियासत सही नहीं है। दोनों को चाहिए लोगों के कल्याण पर जोर दें न कि इस तरह की सियासत करते रहें।

चीन संग अमेरिका को साधने की चुनौती

ब्रह्मा चेलानी

दूसरे कार्यकाल में मोदी के नेतृत्व की परीक्षा इस आधार पर भी होगी कि वह भारत की विदेश नीति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से कैसे निपटते हैं?

तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने धमाकेदार जीत के साथ सत्ता में वापसी कर ली। बौद्धिक जुगाली करने वाले तमाम लोग मोदी को विभाजनकारी राजनीति के लिए आड़े हाथों लेते रहे, लेकिन वे जमीन पर मोदी के पक्ष में चल रही हवा को भांपने में नाकाम रहे। इस प्रचंड जनादेश ने मोदी को घरेलू मोर्चे के साथ-साथ विदेश नीति की प्राथमिकताएं तय करने में एक तरह से खुला हाथ दे दिया है। उन्हें कुछ समय में ही दुनिया के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करनी है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। पहले कार्यकाल की तरह मोदी की विदेश नीति सतर्क व्यावहारिकता के साथ संचालित होगी। निर्णय लेने की मोदी की अनूठी और विशिष्ट शैली है। इसमें उनकी शख्सियत भी असर दिखाती है। अक्सर उनके अप्रत्याशित फैसलों में चौंकाने का भाव भी होता है। इससे मोदी के आलोचकों को उन पर राष्ट्रपति शैली में सरकार चलाने का आरोप लगाने का बहाना मिला जाता है, जबकि हकीकत यह है कि स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री अमूमन राष्ट्रपति की शैली में ही काम करते आए हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नाम शामिल हैं। इस मामले में कमजोर और खंडित जनादेश से बनी सरकारें ही अपवाद हैं।

चुनाव से पहले ही मोदी ने अंतरिक्ष युद्ध को लेकर भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन कर चीन को चेतावनी देने का काम किया था। भारत ने 27 मार्च को अंतरिक्ष में अपने ही एक उपग्रह को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। इस तरह वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में कोई लक्ष्य भेदने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। जैसे उपग्रह-भेदी हथियार के साथ ही भारत ने चीन के खिलाफ अहम प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की वैसे ही चुनावी जीत के बाद विदेश नीति के संदर्भ में मोदी का पहला कदम भी चीन को ध्यान में रखकर उठाया गया। पहले विदेश दौरे के लिए मोदी ने रणनीतिक रूप से हिंद महासागर के द्वीप मालदीव को चुना है। पिछले साल हुए चुनाव में मालदीव की जनता ने चीन समर्थित तानाशाह की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालांकि उससे पहले ही वहां की सरकार कई छोटे-छोटे द्वीप चीन को पट्टे पर दे चुकी थी। मालदीव में लोकतंत्र बहाली के बाद से भारत ने उसे पूरी उदारता से वित्तीय मदद मुहैया कराई है। इससे मालदीव को चीनी कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिली है। सात-आठ जून को मोदी का यह दौरा सांकेतिक रूप से बेहद अहम है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत दुनिया के सबसे छोटे मुस्लिम देश से करेंगे। इससे पहले मालदीव में जिस तानाशाह का शासन था उसके राज में मालदीव दुनिया में आतंकियों की आपूर्ति के लिए कुख्यात हो गया था। प्रति व्यक्ति आबादी के लिहाज से सीरिया और इराक में जिहाद के लिए आतंकी भेजने वाले देशों में मालदीव तब शीर्ष पर था।

अवधेश राजपूत

मोदी ने एक और चतुराई भरा कदम उठाते हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी के लिए बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। मरणासन्न दक्षेस की तुलना में बिम्सटेक संभावनाएं जगाने वाली पहल है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की 'पड़ोसी को प्राथमिकता' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती हैं। इसके उलट दक्षेस भारत को उलझाए रखता है। उसका दायरा भी भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्सटेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है। इतिहास में भारत के मुख्य व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदार पूरब के देश ही थे। पश्चिमी सीमा से तो केवल आततायी अपनी सेनाओं के साथ आक्रमण करते रहे। भारत के रणनीतिक हितों को देखते हुए बिम्सटेक सही है। इससे एबी शिंजो की पहल पर अमेरिकी नेतृत्व वाली 'मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र' वाली रणनीति में भारत की भूमिका का और विस्तार होगा।

दक्षेस नेताओं को न बुलाकर मोदी परेशान करने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को भी दूर रखने में सफल रहे, जिसने उनकी जीत पर उत्तर कोरियाई शैली में बधाई देते हुए चीनी डिजाइन की परमाणु क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। यह परीक्षण ऐसे समय किया गया जब पुलवामा हमले के कारण दोनों देशों में पहले से तनाव बढ़ा हुआ था। पाकिस्तान और चीन मिलकर मोदी के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश करते हैं। यह शायद दुनिया में किसी एक देश को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले पड़ोसियों की जोड़ी मानी जाएगी।

मोदी ने इस साल अक्टूबर में शी चिनफिंग को 'अनौपचारिक सम्मेलन' के लिए भारत बुलाया है। संबंधों में तल्खी दूर करने के लिए इससे पहले चीन के वुहान में दोनों नेता ऐसी एक बैठक कर चुके हैं। चीन को लेकर अमेरिकी नीति में ट्रंप द्वारा किए गए बदलाव से चीन के लिए आक्रामकता की गुंजाइश सीमित हो रही है। भारत इसका लाभ उठा सकता है। अमेरिका से रिश्ते बेहतर होने के बावजूद ट्रंप को साध पाना मोदी के लिए खासा चुनौतीपूर्ण है। ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात पर प्रतिबंध से ट्रंप पहले ही भारत पर बोझ बढ़ा चुके हैं। इसके साथ ही 15 अरब डॉलर के रक्षा सौदे हासिल करने के बावजूद अमेरिका रूस से रक्षा साजोसामान की खरीद में अड़ंगे लगा रहा है। भारतीय बाजार में तार्किक एवं बराबर की भागीदारी न मिलने का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने भारत को मिला जीएसपी का दर्जा भी वापस ले लिया है। इसके तहत भारत अमेरिका से 5.6 अरब डॉलर के तकनीकी उत्पादों का शुल्क मुक्त आयात कर सकता था। पिछले साल अमेरिका ने इस्पात और एल्युमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। जवाबी कार्रवाई के नाम पर भारत ने अमेरिका से होने वाले करोड़ों डॉलर के उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का एलान किया। यह बात अलग है कि दरें बढ़ाने की मियाद आगे बढ़ती गई।

मोदी के दोबारा चुनाव पर जब ट्रंप ने उन्हें बधाई दी तो दोनों नेताओं ने 28-29 जून को ओसाका में आयोजित जी-20 सम्मेलन से इतर बैठक के लिए सहमति जताई। मोदी के विदेश दौरों का आगामी कार्यक्रम काफी व्यस्त है। 14-15 जून को उन्हें किरगिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेना है। चार-छह सितंबर को वह व्लादिवोस्टक में पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसी बीच वाशिंगटन में ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में उनके नेतृत्व की परीक्षा इस पहलू से तय होगी कि वह भारत की विदेश नीति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से कैसे निपटते हैं? अगर वह नाकाम रहते हैं तो उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी, लेकिन यदि वह सफल होते हैं तो फिर इंदिरा गांधी के बाद वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा छाप छोड़ने वाले भारतीय नेता बन जाएंगे।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

संघ से वैचारिक संघर्ष की अधूरी तैयारी

बद्री नारायण

आरएसएस के विरोधी यह समझें तो बेहतर कि यह संगठन अपने को लगातार बदलता चला आ रहा है

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुकाबला करने के लिए दो नए संगठन गठित किए हैं। इनमें एक है जयहिंद वाहिनी, दूसरा है बंग जननी वाहिनी। उन्होंने जयहिंद वाहिनी का अध्यक्ष अपने एक भाई कार्तिक बनर्जी को एवं संयोजक दूसरे भाई गणेश बनर्जी को बनाया है। बंग जननी वाहिनी का अध्यक्ष काकोली दस्तीदार को बनाया गया है। माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस 'जयहिंद' का संबंध सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद के प्रतीकों से जोड़ने की कोशिश करेगी। ममता की तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपना वैचारिक संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही मानते हैं। वामपंथी दल यथा भाकपा, माकपा आदि भी अपनी वैचारिक लड़ाई दक्षिणपंथी राजनीति के वैचारिक आधार रचने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही मानते हैं, किंतु प्रश्न यह उठता है कि ये सभी दल अपना वैचारिक संघर्ष किस आरएसएस से मानते हैं? क्या उस आरएसएस से जो उनकी धारणा का आरएसएस है या उस आरएसएस से जो वह वास्तव में है? उनकी धारणा का आरएसएस वह है जिसे आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व की वामपंथी व्याख्याओं से रचा गया है। इस धारणा को लगातार दोहराते हुए आरएसएस के बारे में एक प्रकार की रूढ़िवादी सोच बना ली गई है। यह सोच आरएसएस की एक छाया का निर्माण करती है। आरएसएस स्वयं को लगातार बदलता और नया करता चला आ रहा है। हो सकता है कि यह नयापन एवं परिवर्तन उसके शरीर का ही परिवर्तन हो, आत्मा का नहीं, परंतु जो राजनीतिक दल अपनी लड़ाई आरएसएस से मानते हैं उन्हें आरएसएस के देह स्वरूप में हो रहे लगातार परिवर्तन को तो समझना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आरएसएस की एक छाया से लड़ते रह जाएंगे। इसके नतीजे में संघ अपने सामाजिक आधार को और फैलाता चला जाएगा।

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व आदि में जहां-जहां संघ ने अपने को फैलाया है वहां उसके विरुद्ध संघर्ष की बात करने वाले राजनीतिक दल सच में जो संघ है, उसके बजाय उसकी छाया से ही लड़ते रहे हैं। हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लोग नाराज हों, पर संघ में हो रहे सतत बदलाव को जाने-समझे बिना एक तरह से इस खुशफहमी में जीना है कि हम संघ के विचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। संघ की शक्ति यह है कि वह अपनी लड़ाई किसी से नहीं मानता। वह अपने लक्ष्य को दृष्टिगत रख अपने प्रसार में लगा हुआ है।

संघ के प्रतिवाद के लिए जयहिंद वाहिनी बनाने वाली ममता बनर्जी यह नहीं समझ पातीं कि संघ की शक्ति डंडे, लाठी में नहीं छुपी है। संघ की पहली शक्ति वह सांस्कृतिक एकाधिकार है जिसकी सतत व्याख्या अंतोनियो ग्राम्शी के सैद्धांतिक प्रतिपादनों से पाई जा सकती है। यह सांस्कृतिक शक्ति धर्म, परंपरा, धार्मिक शास्त्रों-अनुष्ठानों एवं भारतीय पारंपरिक मूल्यों को अपनी भाषा में जोड़ने से संघ को प्राप्त हुई है। इसी कारण वह आज सर्वत्र उपलब्ध होने की क्षमता अर्जित किए हुए है। इसी अंतःशक्ति के कारण संघ व्यापक हिंदू समाज, कठिन भौगोलिक परिक्षेत्र, अल्पसंख्यक समूहों को अपने में जोड़ने में लगा हुआ है।

हाल के समय में संघ क्षेत्रीय संस्कृतियों को भी अपने वैचारिक ढांचे से जोड़ने में सफल होता हुआ दिखा है। संस्कृति की भाषा एवं भाव को अपनी शैली में जोड़ने के कारण उसने एक सांस्कृतिक शक्ति प्राप्त की है। जो भी राजनीतिक दल आरएसएस से वैचारिक प्रतिवाद का दावा कर रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि संघ सरीखी सांस्कृतिक शक्ति एवं सांस्कृतिक भाषा विकसित किए बिना ऐसा कर पाना कठिन है। इस भाषा का निर्माण भारतीय संस्कृति के तत्वों एवं स्रोतों में समाहित होकर ही किया जा सकता है। संघ की एक अन्य शक्ति है उसके संपूर्ण ढांचे में निहित समाहन की शक्ति। संघ में अपने विरोधी तर्कों, ढांचों एवं शक्तियों को समाहित कर लेने की अद्भुत शक्ति है। संघ अपने ढांचे से जरूरी समझौते करके भी जनजातीय समूहों, उत्तर-पूर्व के गैर हिंदू समूहों और अल्पसंख्यकों को अपने से जोड़कर एक 'विस्तृत हिंदुत्व' का निर्माण करने में लगा हुआ है। यह 'इच्छा' जब तक संघ के विरोध में सक्रिय शक्तियों में विकसित नहीं हो पाती तब तक उनके लिए संघ से मुकाबला कठिन है। समाहन की यही शक्ति समाज एवं राजनीति में प्रभावी परंपरा रचती है।

संघ की तीसरी शक्ति है सेवाभावी सामाजिक कार्य। संघ पूरे देश में अनेक सेवाभावी परियोजनाएं चला रहा है। इन सेवाभावी परियोजनाओं के माध्यम से वह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपने में शामिल कर रहा है। सेवाभाव की यह संस्कृति भी उसने भारतीय परंपरा में निहित सेवा एवं दान की भावना से सीखी है। इस पारंपरिक सीख का परिवर्द्धन संघ ने ईसाई मिशनरियों के सेवा कार्य की राजनीति को अप्रासंगिक बनाने के लिए भी किया है। अभी हाल में कुंभ में नेत्र रोगियों के लिए लगाए गए 'नेत्र कुंभ' के जरिये संघ लगभग दो लाख नेत्र रोगियों तक पहुंचने में सफल रहा। इसके लाभार्थियों में हिंदू-मुस्लिम, वंचित, आदिवासी सामाजिक समूहों के लोग शामिल थे।

जहां संघ प्रचारक अपने घर परिवार का मोह छोड़ संगठन के प्रति समर्पित होने का आभास देते हैं वहीं ममता बनर्जी ने जो 'जयहिंद वाहिनी' बनाई उसकी कमान अपने भाइयों को सौंप दी। इस तरह धारणा की लड़ाई में ममता बनर्जी अपनी लड़ाई प्रथम चरण में ही हार बैठीं। संघ प्रचारक जिस त्याग भाव को अपनी छवि से जोड़कर रखते हैं उससे जनता के बीच उनके प्रति भरोसा पैदा होता है। स्पष्ट है कि संघ और भाजपा विरोधी दलों को यह सोचना होगा कि पुरानी भाषा, पुरानी धारणा एवं पुराने हथियार से नित परिवर्तित होते जाने वाले संगठन से सफल प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। संघ से लड़ने के लिए इन दलों को भी नया तन एवं नई आत्मा वाला नया अवतार लेना होगा। सबसे बड़ा अंतर्विरोध है कि जहां ये दल राजनीतिक सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं संघ सामाजिक सत्ता रचने में लगा है। जब उसे अपने किसी प्रचारक में राजनीतिक प्रतिभा एवं आकांक्षा दिखती है तो वह उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देता है। गैर राजनीतिक होने की उसकी यह छवि उसके प्रति जनता में विश्वास सृजित करती है। स्पष्ट है कि राजनीतिक शक्तियों को खुद को सामाजिक अभियानों से जोड़ना होगा।

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

योजनाबद्ध कार्य

किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। उसमें कार्य की प्रकृति, उसमें लगने वाले समय, धन और सामर्थ्य का आकलन शामिल होता है। इससे कार्य में सफलता की सुनिश्चितता बढ़ जाती है। प्रायः लोग कोई कार्य बिना किसी ठोस योजना के शुरू कर देते हैं और असफल होने पर निराश तो होते हैं, साथ ही भाग्य और भगवान को दोष देते हैं। जबकि कहा गया है कि प्रयास करने से भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता या सफलता नहीं मिलती तो कहीं न कहीं स्वयं का दोष है। उसी को बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए भी कहा जा सकता है।

योजनाबद्ध कार्य का उदाहरण भगवान श्रीराम द्वारा कदम-कदम पर प्रस्तुत किया गया। लंका पर आक्रमण के पहले वहां की सारी स्थिति का अध्ययन करने के लिए वह हनुमान जी को लंका भेजते हैं। लंका के भौगोलिक, सामाजिक, सामरिक सारी क्षमता का आकलन कर हनुमान जी विस्तृत जानकारी श्रीराम को देते हैं और जब श्रीराम को खुद लंका जाने की बात आती है तथा बीच में समुद्र पर मार्ग बनाने का प्रश्न उठता है तब उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी तत्काल ही उस कार्य को अंजाम देना चाहते हैं और पुल बनाने का उद्यम करने लगते हैं, लेकिन श्रीराम ने उन्हें किसी तरह की जल्दबाजी से रोक दिया। रामचरितमानस में उल्लेख है कि स्वयं श्रीराम समुद्र तट पर तीन दिन बैठे। इन तीन दिनों में श्रीराम का समुद्र पर पुल बनाने की कार्ययोजना को अंजाम देना ही था। किसी कार्य को शुरू करने में जब व्यक्ति एकाग्र मन से किसी कार्य का चिंतन करता है तो चिंतन में ही अनेक रास्ते निकलते हैं।

जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए सबमें वैज्ञानिकों ने पहले गहरा चिंतन किया। माना जाता है कि ठंडे मन से किसी विषय पर सोचने से सरल उपाय निकल आते हैं, जबकि प्रायः व्यक्ति जल्दबाजी तथा शॉर्टकट रास्ता तलाशता है। होना तो यह चाहिए हर दिन सो कर उठने के बाद जिस भी क्षेत्र में जो लगा है, वह अपने उस दिन के कार्य की सुविचारित योजना बनाए और उसके अनुसार कार्य करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता न मिले। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से कभी कुछ कम सफलता मिले। थोड़ी भी सफलता मिलने से उत्साह बढ़ता है और उत्साह से किया गया कार्य मंजिल तक पहुंचता है।

सलिल पांडेय

फास्ट फूड से बिगड़ती सेहत

अभिजीत मोहन

पिछले कुछ वर्षों में फास्ट फूड में गैर सेहतमंद तत्वों की मात्रा में भारी इजाफा हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है

अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का यह खुलासा चिंतित करने वाला है कि पिछले कुछ वर्षों में फास्ट फूड में गैर सेहतमंद तत्वों की मात्रा में 226 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खाद्य पदार्थ पहले से ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे और अब इन तत्वों की मात्रा में भारी इजाफा स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने यह नतीजा दस प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन के 1787 खाद्य पदार्थों पर अध्ययन के उपरांत निकाला है। शोधकर्ताओं का मानना है कि 1986 से 2016 के बीच इन फास्ट फूड चेन में मेनकोर्स व्यंजन का औसत आकार 39 ग्राम और कैलोरी 90 तक बढ़ी है। साइड कोर्स की बात करें तो आकार में ये चार ग्राम बढ़े हैं जिससे 175 से 217 तक कैलोरी में इजाफा हुआ है। इन फास्ट फूड चेन पर मिलने वाली मिठाइयों का वजन 71 ग्राम और कैलोरी 186 ग्राम तक बढ़ी है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि 1985 की तुलना में जीवनशैली में नकारात्मक बदलाव आया है।

गौर करें तो भारत में भी फास्ट फूड सेवन का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और उसी का नतीजा है कि मोटापा बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि 2025 तक भारत में 1.7 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त होंगे और 184 देशों की सूची में भारत दूसरे पायदान पर होगा। मौजूदा समय में चीन में 1.53 करोड़ बच्चे मोटापे संबंधी बीमारी के शिकार हैं। बीते एक दशक में भारत में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या दोगुनी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में 7.94 करोड़ वयस्क मोटापे से ग्रस्त हैं। चीन दूसरे नंबर पर है जहां 5.73 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। एसोचैम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी कई रिपोर्टों में कहा जा चुका है कि मोटापा का एक प्रमुख कारण फास्ट फूड का सेवन है। चूंकि हर तरह के फास्ट फूड के निर्माण में चीनी से बनने वाली चीजें मसलन सोडा, कैंडी और बेक का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इनका अधिक सेवन करने से मुंह संबंधी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चिकित्सकों का मानना है कि चूंकि आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड में सोडियम की मात्रा अधिक रहती है जो रक्तचाप और स्ट्रोक की संभावना को बढ़ा देती है। शरीर को सेहतमंद रखने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। इससे शरीर का समग्र विकास होता है, लेकिन गौर करें तो फास्ट फूड में विटामिन और खनिज की मात्रा न के बराबर होती है। लिहाजा अधिक फास्ट फूड सेवन करने वाले विटामिन न मिलने के कारण कई किस्म की गंभीर बीमारियों का सामना करते हैं।

आज की तारीख में फास्ट फूड कंपनियों का बाजार 15 हजार करोड़ रुपये के आसपास है और इसमें हर वर्ष 25 फीसद का इजाफा हो रहा है। यहां ध्यान देना होगा कि जब 1972 में फास्ट फूड की शुरुआत हुई तो उसका उद्देश्य यह था कि लोगों को ज्यादा कैलोरी हासिल हो। कंपनियां इस मकसद में तो कामयाब रहीं, लेकिन गुणवत्तापरक पौष्टिक आहार देने के मानक पूरे नहीं किए। उनका एकमात्र मकसद खूब धन कमाना है चाहे उसकी कीमत लोगों को बिगड़ते स्वास्थ्य के रूप में क्यों न चुकानी पड़े।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भाषाई सद्भाव की जरूरत

प्रो. निरंजन कुमार का अपने आलेख 'हिंदी के प्रति अनावश्यक दुराग्रह' में नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को राष्ट्रव्यापी स्तर पर स्कूली शिक्षा में सम्मिलित करने के दक्षिण भारतीय विरोध को राजनीति से प्रेरित भाषाई दुराग्रह मानना उचित प्रतीत होता है। आज हिंदी भाषा भारत के करीब हर प्रदेश में बोली और समझी जाती है। व्यापारिक और राजनीतिक विज्ञापनों में सर्वाधिक रूप से हिंदी भाषा ही प्रयुक्त की जाती है। बावजूद इसके केवल भाषाई स्तर पर अपने को विशिष्ट मानने के दुराग्रहवश हिंदी भाषा का विरोध करना दक्षिणी राज्यों का शगल बन गया है। दक्षिण भारतीय गैर हिंदी भाषी राज्यों के इस भाषाई दुराग्रह के कारण ही हिंदी अपने राष्ट्रभाषा के अधिकार से अब तक वंचित रही है। आखिर कब तक भारत राष्ट्र भाषाई स्तर पर गूंगा बना रहेगा? उम्मीद थी कि मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देगी, लेकिन थोड़े से विरोध प्रदर्शन के बाद नई शिक्षा नीति के प्रारूप से हिंदी भाषा की राष्ट्रव्यापी अनिवार्यता को खत्म करके नव निर्वाचित केंद्र की भाजपा सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर कर दिया है। हिंदी भाषा के प्रति होने वाला यह अन्याय अब हिंदी भाषा भाषियों के लिए असहनीय होता जा रहा है। देश की भाषाई एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है। इस दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना अब समय की मांग है। दक्षिण भारतीय राज्यों को भी अपने भाषाई दुराग्रह से परे होकर हिंदी भाषा के संबंध में लचीला रुख अपनाना चाहिए। आखिर हम भारतवासी अपने देश की सभी भाषाओं का सम्मान करना कब सीखेंगे? अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा सीखना कोई बुरी बात तो नहीं है, फिर हिंदी भाषा सीखने का विरोध क्यों? विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखना लाभदायक होता है। गैर हिंदी भाषी लोग इसी सद्भाव से हिंदी भाषा को पढ़ने-पढ़ाने में संकोच न करें, क्योंकि इस तरह के भाषाई सद्भाव से ही हिंदी को घोषित रूप से राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो सकता है।

pandeyvp1960@gmail.com

समरसता की राह पर चलना होगा

संपादकीय आलेख 'क्षणिक गठबंधन' में सपा-बसपा के चुनावी समीकरण का सटीक आकलन किया गया है। संपादक का यह कथन काफी हद तक सही है कि यदि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होती तो स्थिति थोड़ी अलग हो सकती थी। बेशक कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के लिए उत्सुक थी, लेकिन सपा-बसपा ने उसे भाव ही नहीं दिया। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का परिणाम भुगत चुके थे, जहां वे सत्ता से बेदखल हो गए थे। शायद इसी कटु अनुभव के कारण सपा-बसपा ने कांग्रेस से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी होगी। किंतु मोदी लहर के आगे गठबंधन भी कोई चमत्कार नहीं दिखा सका। वैसे भी अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों के बेमेल गठबंधन कभी स्थायी नहीं होते, बिखरना ही उनकी नियति है। इसीलिए मायावती ने भविष्य की संभावना को देखते हुए गठबंधन का पटाक्षेप कर दिया है। यदि सपा-बसपा को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रभावी प्रदर्शन करना है तो उन्हें जातिवाद के बंधन को तोड़ कर समरसता की राह पर चलना सीखना होगा।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

नए परिसीमन की आस

जम्मू-कश्मीर में नवंबर 2019 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव पूर्व परिसीमन पर कुछ कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 2002 में नेशनल कांफ्रेंस ने राज्य के संविधान में ही परिवर्तन कर 2026 तक जम्मू-कश्मीर के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। 87 सीटों वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अकेले कश्मीर में 46 सीटों की नुमाइंदगी को राजनीतिक तौर पर जानबूझकर ज्यादा केंद्रित रखा गया है ताकि कश्मीर राजनीति की धुरी बने रहे और राजनीतिक गुणा भाग के साथ सत्ता प्रभुत्व का भी खेल खेला जाए। जबकि 37 विधानसभा सीटों वाले जम्मू और 4 विधानसभा सीटों वाले लद्दाख जैसे बड़े क्षेत्र को राजनीतिक तौर पर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन की पहल से जहां अनुसूचित जाति व जनजातियों को आरक्षण की नई व्यवस्था में लाया जा सकेगा, वहीं जम्मू एवं लद्दाख संभाग का विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय